बिहार विधान-सभा वादवृत्त ।

वृहस्पतिवार, तिथि ५ अक्टूबर १६६१ ।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में वहस्पतिवार तिथि ५ अक्टूबर १६६१ को पूर्वाह्न ११ बजे सभापति श्री रामनारायण मंडल के सभापतित्व में हुआ ।

स्थगन प्रस्ताव ।

ADJOURNMENT MOTION.

सभापति (श्री राम नरायण मंडल)—एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री देवनन्दन प्रसाद का है । इस प्रकार का कार्य-स्थगन प्रस्ताव पहले एक बार नामंजूर हो चुका है । इस कार्यस्थगन प्रस्ताव में जो कहा गया है उसे मालूम होता है कि यह एक प्राकृतिक विपत्ति है और बाढ़ पर सरकार का कोई कंट्रोल भी नहीं है...

श्री देवनन्दन प्रसाद—सभापति महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री वहां गए थे । तीन बार पहले भी इस प्रकार की बाढ़ आ चकी है और उसके लिए लिखापढ़ी भी हुई लेकिन कुछ इंतजाम नहीं हो सका । अगर सरकार तीन रोज पहले सचेष्ट हो जाती तो ऐसी हालत नहीं होती ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल)—यह एक प्राकृतिक विपत्ति की बात है। इसलिए मैं इस स्थगन-प्रस्ताव को नामंजूर करता हूँ ।

बिहार पुलिस कमीशन का प्रतिवेदन ।

REPORT OF BIHAR POLICE COMMISSION.

श्री केदार पांडे—महोदय मैं बिहार पुलिस कमीशन की सन् १६६१ का प्रतिवेदन सभा के समक्ष पेश करता हूँ ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना पर वाद-विवाद।

DISCUSSION ON THE THIRD FIVE-YEAR PLAN.

श्रीमती अनुसूया देवी—सभापति महोदय, अभी में इंडस्ट्रीज के बारे में बोल रही थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्रीज में भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर ज्यादा-से-ज्यादा जोर दिया गया जिसमें बेरोजगार लोगों को रोजी मिले और वे स्वावलंबी बनें।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में दिया हुआ है कि द्वितीय योजना काल में इतनी-बेरोजगारी रह गयी और इन लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हो सका। उनको स्मॉल-स्केल इंडस्ट्रीज में भी नहीं लगाया जा सका। इतने लोगों को क्यों नहीं रोजगारी मिल सका अगर सरकार इस बात को जानना चाहती तो इसकी वजह जान सकती थी। मेरा कहना है कि सरकार ने सेकेंड फाइव-इयर प्लान काल में इंडस्ट्रीज पर शायद काफी ध्यान नहीं दिया। मेरे ख्याल में जो छोटी छोटी पूंजी लेकर काम करनेवाले हैं उनको पूरी सुविधा नहीं दी गई जिसके कारण उनका चलना मुश्किल है। बड़े पूंजीपतियों की तरह उनके पास पूंजी नहीं है कि वर्षों तक इंतजार करते रहेंगे। मिशाल के तौर पर में आपके सामने एक बात रखना चाहती हूँ। हैन्डलूम के बारे में सेकेंड प्लैन में काफी चर्चा की गई और काफी प्रयास सरकार की ओर से की गई। हैन्डलूम से उद्योग तो बढ़ा जरूर लेकिन जो पावर लूम दी गई उसके बारे में कहना यह है कि पावर लूम देने के बाद पावर देने की व्यवस्था भी होनी चाहिये थी। मगर पावर न मिलने के कारण लोग निरुत्साह होकर दूसरे-दूसरे काम में लग गये। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये थी कि छोटे-छोटे उद्योगपति जो हैं, जो छोटे-छोटे पूंजी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी सुविधा को देखते हुए उनके लिए पूरी व्यवस्था पहले ही से कर लेती। आप लूम दे दें और उसके बाद पावर नहीं प्राप्त हो, आप उनको मशीन दे दें और उसके बाद बिजली नहीं प्राप्त हो तो वे कहां से इंस्टौलमेंट देंगे? जो इंडस्ट्रीयल स्टेट्स हैं, जो छोटे-छोटे उद्योगपति हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से आश्वासन मिला था कि जो बाहर से टेंडर पड़ेंगे और बिहार से जो टेंडर पड़ेंगे उनमें इनको १२॥ (साढ़े बारह) प्रतिशत की छूट दी जायगी जिससे कि बिहार के उद्योगपति आगे बढ़ सकें और बिहार में बेकारी दूर हो। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अगर सरकार हर विभाग में किसको-किसको ऑर्डर दिया गया है, इसकी लिस्ट मंगाकर देखे तो मालूम होगा कि १२॥ (साढ़े बारह) प्रतिशत छूट देने के बाद संतोषप्रद फल नहीं मिला। इनसुलेटेड पीन के लिए सिक्यूरिटी मनी जमा था, मगर बाहर के लोगों को आर्डर मिला। इसी तरह और भी चीज हैं जो सरकार के सामने है। सरकार को चाहिये कि उद्योगपति के लिए बिजली की व्यवस्था करें, पहले से उनके लिए बिजली रिजर्व करदें, तब ही उनको मिल सकता है। बिजली के बारे में सरकार ने कहा है कि थर्ड प्लैन में भी कुछ कमी रह जायगी। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर ज्यादा आकर्षित करना चाहती हूँ कि कम से-कम उनके लिए बिजली का पूरा इंतजाम पहले से कर रखें।

दूसरी बात जो मैं सरकार के सामने रखना चाहती हूँ वह यह है कि कुछ दिन पहले प्रश्नोत्तर के सिलसिले में बताया गया था कि सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने

के लिए यहां से दो व्यक्ति को बाहर भेजा गया है। जो बात बीत गई उसको जाने दीजिए, मगर आगे के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि थर्ड प्लैन में ऐसे लोगों को ही विदेश भेजा जाय जिनका प्रशिक्षण बिहार में या भारतवर्ष के दूसरी जगह में नहीं हो सकता है और साथ-साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाय कि इस तरह के प्रशिक्षण से हमारे बिहार को फायदा होना चाहिए।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल)—आपका समय पूरा हो गया है। आप अब बैठ जायं।

श्रीमती अनुसूया देवी—मैं चाहती थी कि और कुछ विषय पर बोलूं मगर जब समय पूरा हो गया तो एक विषय पर बोल कर मैं एक मिनट में बैठ जाऊंगी।

शिक्षा विभाग के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि थर्ड प्लैन में यह लिखा गया है कि मिनिमम वेज ४० रुपया होगा और शिक्षकों के ५० रुपया रखा गया है। इस तरह की भावना शिक्षक के साथ रखी जाय तो मेरी समझ में यह बहुत बुरी भावना उनके प्रति है। इस चीज को प्लैन में मेंशन ही नहीं करना चाहिए था। मैं समझती हूँ कि जब बाहर सर्कुलर भेजा जायगा तो इन शब्दों को हटा दिये जायेंगे। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए यह जरूरी है कि अन्य कर्मचारी को जो सुविधा प्राप्त है वह उनको भी प्राप्त कराया जाय तथा उनकी मानसिक चिन्ता को दूर करने की कोशिश की जाय।

श्री शालिग्राम सिंह—माननीय सभापति महोदय, आज दो दिन से थर्ड फाईव-इयर प्लैन पर वाद-विवाद चल रहा है। पहले रोज जब डिप्टी मिनिस्टर साहब व्याख्यान कर रहे थे तो उन्होंने एक मार्के की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रथम प्लैन में बेकारी की संख्या ५ लाख थी दूसरी प्लैन में वह बढ़कर ९ लाख हो गई और तीसरी प्लैन में अनुमान यह है कि बेकारी की संख्या १७ लाख हो जायगी। होना यह चाहिये था कि ज्यों-ज्यों हमारे प्लैन का नंबर बढ़ता जाय बेकारी की संख्या घटती जाय लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है हमारी सरकार की जो नीति है, खासकर उद्योग के संबंध में वह ठोस नीति न होने के कारण बेकारी राज्य में बढ़ती जा रही है। प्रथम प्लैन-काल में आपने ट्रान्सपोर्ट का राष्ट्रीयकरण किया और उसका नतीजा यह हुआ कि ७७ करोड़ रुपया को सिर्फ यातायात पर लगा दिया जिसे दूसरे डेवलपमेंट के काम में लगाया जा सकता था। इसी तरह से राष्ट्रीयकरण का काम होगा तो गरीब किसान के पैसे का दुरुपयोग होगा। मेरा कहना है कि आप इस तरह के राष्ट्रीयकरण के काम को बन्द कर दें। आज भी हमारे राज्य में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ-कुछ इन्डस्ट्रीज को चला सकते हैं। हमारे छोटानागपुर में बांस और सवाई घास बहुत होता है। इससे वहां कई पेपर मील चल सकते हैं। अगर आप प्राइवेट आदमी को इस काम को करने दें तो आज भी लोग इसमें काफी पैसे लगाने के लिये तैयार हैं। आज सरकार जमीन्दारों को बौन्ड दे रही है।

अगर सरकार प्रोत्साहन दे कि जमींदारों को जो बौंड दिये जाते हैं वे पेपर इंडस्ट्री में लगायें और उस इंडस्ट्रीज में सरकार रोकथाम नहीं करेगी तो हम समझते हैं कि छोटानागपुर में पेपर मिल बहुत अच्छी तरह चल सकती है।

इसी तरह का माइका इंडस्ट्री की तरफ भी, जिससे हिन्दुस्तान में काफी डालर प्राप्त होता है, सरकार का ध्यान नहीं है। आज जंगलों और पहाड़ों से माइका निकाला जाता

है लेकिन इसके लिये यातायात की सुविधा नहीं है तृतीय योजना में भी हम देखते हैं कि जंगल और पहाड़ों से जो माइका निकाला जाता है उसके लिये यातायात की कोई सुविधा का प्रबंध नहीं है।

कोयला की खान के बारे में हम यह देखते हैं कि जो प्राइवेट लोग कोयला की खान चला रहे हैं उनके लिये यातायात की सुविधा नहीं है जिसके कारण उन्हें बड़ी कठिनाई होती है। सरकार अगर इसकी ध्यान दे तो हम समझते हैं कि कोयला और माइका की खानों में काफी तरक्की हो सकती है और समाज में बेकारी की समस्या हल हो सकती है। हम देखते हैं कि माइका और कोयला की खानों में जो बिजली मिलनी चाहिये वह भी नहीं मिलती तो फिर कैसे उम्मीद की जा सकती है कि इन इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन मिलेगा। छोटानागपुर में तिलैया, मैथन और पंचेत डैम बने हैं लेकिन जो बिजली यहां पैदा होती है वह बाहर बंगाल में चली जाती है और यहां के लोगों को नहीं मिलती। यहां की जो आवश्यकतायें हैं कम से कम उतनी बिजली तो मिलनी चाहिये। इन चीजों की तरफ अगर सरकार ध्यान दे तो इंडस्ट्रीज को काफी प्रोत्साहन मिल सकता है और बेकारी की समस्या भी हल हो सकती है।

हमारा सूबा कृषि प्रधान सूबा है। सारे भारतवर्ष में ७२ परसेंट और बिहार में ८० परसेंट किसान हैं लेकिन सिंचाई का अच्छा प्रबंध नहीं है। तृतीय योजना शुरु हो गई लेकिन छोटानागपुर में सिंचाई का कोई खास प्रबंध नहीं हुआ। हम मानते हैं कि यहां की भौगोलिक स्थिति उत्तर बिहार जैसी नहीं है लेकिन बहुत सी छोटी-छोटी नदियां यहां हैं जिन्हें बांध कर सिंचाई के काम में लाया जा सकता है लेकिन सरकार को इसका ज्ञान नहीं है। १९५९ में हमारे क्षेत्र में सिंचाई मंत्री गये थे तो उन्होंने कहा था कि एक अफसर बहाल कर देंगे जो तमाम सबडिवीजन की नदियों की जांच-पड़ताल करेंगे और जहां संभव होगा वहां सिंचाई का इंतजाम किया जायेगा। आश्वासन दिए हुए कई महीने हो रहे हैं। १९६२ का एलेक्शन भी आ रहा है दो साल हो गए लेकिन न वहां इंजीनियर भेजा गया और न कोई प्रबन्ध ही हुआ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल)—आपका समय हो गया।

श्री शालिग्राम सिंह—दो मिनट और।

अब मैं यातायात की बात कुछ कहना चाहता हूं। द्वितीय योजना में उत्तर बिहार में बहुत सी पक्की सड़कें बनीं लेकिन छोटानागपुर में जहां काफी माइन्स और मिनरल्स हैं वहां कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारे इलाके में प्रतापपुर पिछड़ा इलाका है वहां सड़क बनने को थी भी लेकिन अभी तक नहीं बनी। फिर चतरा से चौपारण तक जो सड़क है यह सबडिवीजन को कनेक्ट करती है। बहुत पुरानी सड़क है और ग्रैंड ट्रंक रोड से कनेक्टेड है इसको बनाना चाहिये लेकिन इसे तृतीय योजना में भी नहीं लिया गया है। सरकार को चाहिये कि इन सड़कों को तृतीय योजना में ले लें ताकि यातायात की सुविधा पूरी हो।

श्री कपूरी ठाकुर—मेरा प्रस्ताव है कि चूंकि इस सदन के बहुत सदस्य तृतीय योजना पर बोलना चाहते हैं और चूंकि यह ५ वर्ष के लिये एक निश्चित नीति है, निश्चित प्रोग्राम है, विकास के काम के बारे में है इसलिये मैं समझता हूं कि अधिक से अधिक सदस्य इस पर अपनी राय दें, अधिक से अधिक व्यक्ति को अपनी राय व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिये और इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि तृतीय योजना पर बहस

के लिये दो रोज का समय और बढ़ा दिया जाय यानी आज ५, १० तक का प्रोग्राम बनाया है, ११ और १२ तृतीय योजना के लिये और १३ को प्रिविलेज कमिटी के लिये रखा जाय और उसके बाद सेशन नहीं बढ़ाया जाय।

श्री हरिचरण सोय—श्री कर्पूरी ठाकुर ने जो कहा है वह तो सही है लेकिन हमलोगों का कहना है अब तक जो समय दिया है उसका सिलसिला डिस्ट्रिक्टवाइज होना चाहिये। यह भी पता चलता है कि अपोजीशन का मतलब उधर से ही आप समझते हैं क्योंकि हमलोग चेम्बर में बात करने के लिये जाते हैं तो भी समय नहीं दिया जाता है। झारखंड पार्टी और जनता पार्टी के लिये समय का निर्धारण हो जाना चाहिये।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल)—कोई भी माननीय सदस्य ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। यह चेयर पर आक्षेप है।

श्री हरिचरण सोय—तो हमलोग कहां दर्खास्त करें ?

सभापति (श्री राम नारायण मंडल)—आप चेयर से अनुरोध कर सकते हैं लेकिन ऐसी बात नहीं बोल सकते हैं। यह आक्षेप है।

श्री हरिचरण सोय—मैं अनुरोध ही कर रहा हूं।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल)—आपने अनुरोध नहीं किया है, चेयर पर आक्षेप किया है। आप अपनी बात को वापस लें।

श्री हरिचरण सोय—मैं वापस लेता हूं। लेकिन इस बात के साथ कि इस ओर भी चेयर से समय मिले।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल)—श्री कर्पूरी ठाकुर के प्रस्ताव पर विचार करके मैं कल कहूंगा।

श्री कर्पूरी ठाकुर—तो हम मान लें आज कनक्लूड नहीं करेंगे। माननीय सदस्यों की इच्छाओं का समादर करना और उस पर अपना निर्णय देना तो आपका ही काम है। आप कहेंगे तो सरकार तो मान ही जायगी। जब सभी सदस्य कह रहे हैं तो सरकार क्यों नहीं मानेगी।

श्री जवार हुसेन—एक बार जब सरकार ने वक्त बढ़ाने की दर्खास्त की तो अपोजीशन के लोगों ने तथा और-और लोगों ने भी कहा कि आखिरी फैसला करना चाहिये और हमलोगों ने आखिरी फैसला कर लिया कि १० तारीख के बाद सेशन नहीं बढ़ेगा।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल)—श्री कर्पूरी ठाकुर का कहना है कि यह बहुत इम्पोर्टेन्ट विषय है इसलिये दो दिनों का समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री जब्बार हुसेन—जिस वक्त हमलोगों ने फैसला लिया था उस समय भी यह प्लान हमलोगों के सामने था और इसकी महत्ता थी उस पर भी फैसला हुआ था कि १० तारीख के बाद सेशन नहीं बढ़ेगा और उसके मुताबिक १० के बाद नहीं बढ़ना चाहिये। यह मुमकिन भी नहीं है कि १० तारीख के बाद बढ़ाया जाय। अगर टाइम बढ़ाना चाहें तो एक-एक घंटा समय बढ़ा करके कर सकते हैं।

श्री कर्पूरी ठाकुर—सभी मेम्बर चाहते हैं इसलिये समय बढ़ना ही चाहिए।

श्री जब्बार हुसेन—सभापति महोदय, अभी जिस तरह से सदन में विवाद चल रहा है, मैं और लोगों से सलाह कर लेता हूं उसके बाद जवाब दूंगा।

श्री राम जनम ओझा—सभापति जी, ११ बजे से ४ बजे तक रहना सदस्यों के लिये जरूरी है।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल)—मैं एक घोषणा करता हूं कि आज सभा की बैठक ५ बजे तक होगी।

श्री नागेश्वर राय—श्री कर्पूरी जी का जो प्रस्ताव है उसको सरकार नहीं मानती है, इससे साफ जाहिर है कि सरकार हमलोगों की बातों की कुछ भी मान्यता नहीं देती है।

*श्री यदुनन्दन तिवारी—सभापति महोदय, तीसरी पंचवर्षीय योजना से हमारे जिले क्या होनेवाला है उसपर सदन का ध्यान ले जाता हूं। इसके विषय में बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं इसलिये हमलोगों को कहना पड़ता है कि हमारे यहां क्या होना चाहिये और क्या नहीं हो रहा है।

छोटानागपुर के बारे में सरकार कहती है कि वहां इन्डस्ट्रीज पनप सकती है और उत्तर बिहार में खेती की तरक्की हो सकती है। यह दुःखद घटना है। उत्तर बिहार में कृषि के लिये जितनी गुंजाइश है उससे कहीं अधिक गुंजाइश छोटानागपुर में है। छोटानागपुर में नयी जमीन खेती के लायक बनायी जा रही है, काफी इन्तजाम है, काफी जमीन है। हां उत्तर बिहार की नदियों में सालों भर पानी रहता है और दक्षिण बिहार की नदियों में नहीं। लेकिन सरकार उन नदियों को बांध कर उनसे सिंचाई का काम ले सकती है। वर्षा में अधिक पानी जो आता है उसको रोककर रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर सिंचाई का काम लिया जा सकता है। उत्तर बिहार में बाढ़ आती है तो बहुत हल्ला होता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सोन नदी के पानी से दक्षिण बिहार में कुछ क्षति होती है इसपर उसका ध्यान कभी गया है या नहीं। यह बात सही है कि गंडक और कोसी योजना बन रही है, बनें लेकिन सोन, कोयल घनहा रेंड, बीज नदियों से काफी क्षति होती है इसपर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। उस क्षेत्र के लोग इनसे काफी परेशान रहते हैं। यह बात सही नहीं है कि जहां अधिक खर्च हो वहां काम छोड़ दिया जाय और जहां कम खर्च हो वहां काम किया जाय। आप किसी तराजू पर एक मन एक ओर रखिये और दूसरी ओर एक सेर रख दीजिए तो दोनों बराबर कैसे हो सकता है। क्या सरकार कभी यह सोचती है कि छोटानागपुर और पलामू उत्तर बिहार की बराबरी कर सकता है। मैं

सरकार से जानना चाहता हूं कि केरल और आंध्र में ऐसी स्कीमें ली गयी हैं या नहीं जहां प्रति एकड़ ६०० से १,००० रु० तक खर्च हुआ है। अपने यहां भी कुछ काम ऐसे हुए हैं जहां २,५०० रु० प्रति एकड़ खर्च हो चुके हैं लेकिन २ एकड़ में भी सिंचाई नहीं हो सकी है। पलामू जिले में कोई ऐसी जमीन खेती के लायक नहीं है जो सी-लेवल (sea-level) से १,५०० फीट ऊंची न हो।

सरकार अधिक खर्च की बात करती है लेकिन उसको सोचना चाहिये कि जब वहां नदियों को बांधा जायगा तो उनसे सिंचाई भी होगी और बिजली भी पैदा होगी। इस प्रकार जो खर्च होगा उससे कहीं अधिक लाभ होगा।

मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि पलामू जिले में ८,००० एकड़ ऐसी जमीन है जहां ऐस्योर्ड इरिगेशन हो सकती है।

मगर ऐसी स्थिति में जिसमें एक लाख एकड़ जमीन में एशिओर्ड इरिगेशन नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गयी लेकिन सरकार ने क्या किया है? वही जो पुराने औजार थे उन्हीं की मरम्मत कर दिया गया है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि वहां ८ लाख एकड़ जमीन पड़ी हुई है, वहां स्थानीय टेकनिशियन हैं उनसे राय ली जाय कि इसके डेवलप का कैसे इंतजाम हो लेकिन दिक्कत यह है कि उनके मुंह बन्द रहते हैं, वे समझते हैं कि अगर हमने स्कीम बताई जो हाईयर अफसर की हो तो लोग नाराज हो जायेंगे, यही तो हालत है तब कैसे कोई काम में तरक्की हो सकती है। हमारे उपमंत्री श्री केदार पाण्डे पलामू में गये थे जहां एक नदी है उसको उन्होंने देखा। इसमें इन्वेस्टीगेट करने में मुश्किल से ३-४ करोड़ रुपये का खर्च है। अगर इस स्कीम को सफल बनाया जाय तो इससे एक लाख एकड़ जमीन उस नदी से इरिगेट हो सकती है। इसके इलावे तीन और नदियां हैं एक है कोयल और दूसरी है कनार तीसरी का नाम याद नहीं है। इस सरकार के एक अफसर सन् १९५२ में गये थे तो उन्होंने इन दो नदियों के बारे में यह रिपोर्ट दी थी बिजली के बारे में। इन नदियों से एक लाख किलोवाट से अधिक बिजली प्राप्त होने की सम्भावना है लेकिन दिक्कत यह है कि इस काम के लिये कौन बीड़ा उठाता है ऊपर से दबाव नहीं है ताकि यह काम हो सके। आपकी दस वर्षों की योजना की अवधि समाप्त भी हो गई, लेकिन नदियों के बारे में योजना पूरी नहीं हो सकी है। कोई भी स्थान हमारे जिला में १,३०० फीट समुद्र की ऊंचाई से कम नहीं है और नदियों की धारा १,६०० फीट और १,००० फीट है अगर इन नदियों पर बांध बांधा जाय तो जमीन जो ७०० फीट और ८,६०० फीट नदियों से नीचे पड़ती है आसानी के साथ पटवन का काम किया जा सकता है। अगर कोनार और कोयल नदियों में दिलचस्पी ली जाये तो इससे वहां के लोगों को बहुत ही सफलता मिलेगी।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल)—आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री यदुनन्दन तिवारी—सभापति महोदय, यह बात सही है कि हमारे जिले के लोगों को किसी को भी कुछ टाईम नहीं दिया गया है, इसलिये हमें बेशी टाइम इसपर बोलने के लिये दिया जाय।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल)—समय आपको नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जो समय आपको दिया गया है वह समाप्त हो रहा है इसलिये आप अपना भाषण जल्द समाप्त करें।

श्री यदुनन्दन तिवारी—अच्छी बात है। हमने कहा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में अमानत की योजना ली जा सकती है यह सही है कि कोनार की योजना चालू नहीं की जा सकती है लेकिन उसका इन्वेस्टीगेशन हो सकता है।

अब मैं कुछ सड़क की बात कह देना चाहता हूं। इसमें डेभलपमेंट नहीं होने का कारण यह है कि सड़क के बनाने का काम पी० डब्लू० डी० करती है। जो मंत्री महोदय हैं उनका पैर कड़ी जमीन पर रखा नहीं जाता है जिसकी वजह वे दौरा नहीं करते हैं। जबतक पी० डब्लू डी० को सड़क बना कर नहीं दी जाती है उस वक्त तक उसपर काम नहीं होता है। उनके अफसर हैं, कर्मचारी हैं, जिन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी जगह वे नहीं जाते हैं। पांच-पांच महीनों तक वे नहीं जा सकते हैं। बरसात में तो और भी नहीं जा सकते हैं। पैदल जाने में उनको दिक्कत होती है। ये सब कारण हैं, जिसकी वजह से सड़क नहीं बन पाती है।

मझगांवा को छोड़ दिया गया है। शायद तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह संभव है। इससे लोगों को फायदा हो सकता है। पांडे जी से हमने नगर से करौनी तक के सड़क के लिये कहा था। बरसात में वहां जाना मुश्किल होता है। इसके लिये इन्क्वायरी भी हुई। पांडे जी ने कहा था कि यह सड़क होना चाहिये। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दूसरी सड़क ली गयी जो बनी बनायी सड़क थी। इसलिये यह ली गयी कि अफसरों का माइलेज बने और उनकी गाड़ियां दौड़े। मुझे पता चला है कि नगर से करौनी तक की सड़क की तृतीय पंचवर्षीय योजना में नहीं है। अगर यह सड़क ले लिया जाता तो ५० मील का फायदा होता। छोटानागपुर में बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज हैं लेकिन अन-इम्पलायमेंट का सवाल हल नहीं हो रहा है। छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज नहीं खुल रही है। बड़ी इन्डस्ट्रियों में लोहा पैदा होता है लेकिन कोई लोहा नहीं खायेगा। इसलिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज की व्यवस्था होनी चाहिये। हमारे यहां हड्डी है, उससे बनने वाली चीजों की शिक्षा देने की व्यवस्था हमारे प्रान्त में नहीं है। हमारे यहां चाइना मिट्टी होती है उसके लिये भी कोई शिक्षा नहीं है जिससे लोग लाभ उठा सकें। चपड़ा भी हमारे यहां काफी मात्रा में उपलब्ध है। उससे भी कितनी चीजें बनायी जा सकती हैं लेकिन उसके लिये भी कोई अच्छी शिक्षा नहीं है जिससे लाभ उठाया जा सके। सोन सुतरी से भले ही लोग कुछ कमा लें, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। सरकार का ध्यान मैं इन सब बातों की ओर आकृष्ट करूंगा और चाहूंगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना से लोगों की जो आशा है वह पूरी हो।

श्रीमती मनोरमा देवी—सभापति जी, मैं सरकार द्वारा उपस्थित तृतीय पंचवर्षीय योजना पर अपना विचार प्रकट करना चाहती हूं। इसके पहले मैं पहली और दूसरी योजना जो समाप्त हुई है उसकी ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहती हूं कि किस प्रकार हमारी सरकार इसमें सफल हुई है और उससे जनता को लाभ पहुंचा है। आज प्रान्त में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और अफसरान उसपर ध्यान नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि इससे हमको क्या गरज है। इसका नतीजा है कि चोरी डकैती बढ़ रही है। जनता तबाह है। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि अगर सरकार कड़ाई के साथ इस ओर ध्यान नहीं देती है तो यह तृतीय योजना सफल नहीं हो सकती है।

सभापति महोदय, कृषि के बारे में पूरा ध्यान नहीं दिया गया है जिससे जनता को फायदा नहीं हो सका है। मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि कृषि की जितनी छोटी-छोटी स्कीम हैं उनको पूरा करें ताकि किसानों को फायदा हो सके।

सड़क के बारे में कुछ भी काम देहातों में नहीं हुआ है। एक गांव से दूसरे गांव में जाना मुश्किल है। पटने में जो बोरिंग रोड पर कैनाल है उसके बगल में जो सड़क है उसकी हालत खराब है। सरकार ने लाखों लाख रुपया इस सड़क पर पानी की तरह बहाया लेकिन वह सफल नहीं हुई। हथिया में बारिश हुई है और जो बाढ़ आयी है उससे पटने के उत्तरी हिस्से की बर्बादी हुई है और इससे किसानों को बहुत नुक्शान पहुंचा है। आप जानते हैं कि जनता किस तरह परेशान है। सरकार को इन सब बातों की तरफ ध्यान देना चाहिये।

अब मैं स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहती हूं। पटना में सबसे बड़ा अस्पताल पटना जेनरल अस्पताल है। जिसकी हालत बड़ी दयनीय है। मैंने कई बार मिनिस्टर साहब का ध्यान खींचा है। लेकिन उनके रहने के लिये कोई जगह नहीं है। बरसात में, गर्मी में और जाड़े के दिनों में लोगों को बड़ी दिक्कत होती है और लोग पेड़ के नीचे रहते हैं। पटना में जो टी० बी० अस्पताल है उसमें औरत और मर्द के लिये अलग प्रबन्ध नहीं है जिससे औरत मरीजों को बड़ी दिक्कत होती है। मैं सरकार से कहूंगी कि टी० बी० अस्पताल में जगह बढ़ावें ताकि लोगों की दिक्कत दूर हो।

हम लोगों ने देखा है कि हमारे डॉक्टर लोग दिहातों में जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वहां अच्छे मकान, अच्छी सड़क और बिजली का इन्तजाम नहीं रहता है। इस कारण देहाती क्षेत्र में रहनेवाले लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। मेरी राय है कि मेडिकल कॉलेज में पढ़नेवाले लड़कों पर यह शर्त्त लगा दी जाय कि जबतक वे दिहात में कुछ समय तक काम नहीं करेंगे तबतक उनको डॉक्टरी की डिग्री नहीं मिलेगी। साथ ही यह भी आवश्यक है कि देहाती इलाकों में मुफ्त दवा दी जाय।

आजकल शिक्षा की बहुत रद्दी हालत हो गई है हालांकि जब से हमारे मौजूदा शिक्षामंत्री ने अपना पद ग्रहण किया है तब से कुछ सुधार हुआ है। स्त्रियों के शिक्षा के बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती है और इसलिये यह जरूरी है कि सरकार स्त्री शिक्षा पर काफी ध्यान दे। साथ ही शिक्षिकाओं के लिये आवास स्थान भी होना चाहिये क्योंकि उसके बिना उनको बड़ी असुविधा होती है। लड़कियां जो कॉलेज से पास करती हैं वे बेरोजगार रहती हैं और इधर उधर मारी फिरती हैं। सरकार को चाहिये कि उनको रोजगार दे।

हमारे यहां बहुत से कल-कारखाने खुल रहे हैं लेकिन बिहारी लोग वहां नहीं रोजगार पाते हैं क्योंकि कहा जाता है कि बिहार में क्वालिफाएड लोग नहीं हैं। जबतक किसी को कोई मौका नहीं दिया जायेगा तबतक कैसे क्वालिफाई करेगा। सरकार को चाहिये कि बिहारियों को हर तरह से प्रोत्साहन दे क्योंकि यह बात ठीक नहीं है कि इन्डस्ट्रिज हमारे यहां खुलें और नौकरियां दूसरे प्रदेश वाले पावें।

हमारे क्षेत्र बिहटा के इलाके में परेओ नामक एक गांव है जहां १५० घर ठठेरा बरतन बनाने का काम करते हैं। उनको सरकार के द्वारा कोई सुविधा नहीं मिलती है। कुछ लोग बम्बई से आये और कुछ कागज पर लिख कर उनके संबंध में ले गये लेकिन आजतक उनको कुछ नहीं मिला। सरकार को चाहिये कि इनकी सहायता करे ताकि इनके रोजगार में तरक्की आवे।

आजकल हमारे प्रान्त की आबादी बढ़ रही है और दूसरी ओर खाने पीने की भी सुव्यवस्था नहीं है, जिसके कारण बहुत लोग रोग के शिकार बनते हैं। सरकार को चाहिये कि दवादारू का अच्छा इन्तजाम करे ताकि लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। परिवार नियोजन के लिये ऐसा करना चाहिये कि इसके बारे में प्रोपगंडा करने से लोग

तैयार हो जायेंगे और दिहात के रहने वालों को पटना आने में बड़ी दिक्कत है इसलिये उनके लिये कुछ पैसे का इंतजाम हो जाय तो वह लोग कर लेंगे ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल)—आपका समय हो गया ।

श्री सनातन समद—सभापति महोदय, आज सदन में तृतीय पंचवर्षीय योजना पर बहस

चल रही है । इसके पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना चली, उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना आयी और उसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है । योजना एक अच्छी चीज है । हमारा हिन्दुस्तान तरक्की करे, तरक्की करना ही चाहिये लेकिन साथ-साथ हमारे छोटानागपुर और संथाल परगना की हालत यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में मयुराक्षी डैम बना और सरकार ने यह कहा कि जब यह डैम बनकर तैयार हो जायगा तो आपके घर-घर में दरवाजे-दरवाजे पर बिजली पहुंच जायगी और सिंचाई के लिये हम पानी भी देंगे । मयुराक्षी डैम भी हमने देखा । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हजारीबाग में तिलैया डैम भी बना । उसमें भी हमें यही आशा दी गयी, लेकिन आज-तक डी० व्ही० सी० से हमारे घर-घर में बिजली नहीं है और छोटे-छोटे कारखानों भी नहीं खुले हैं जिनके बारे में आश्वासन मिला था । सरकार ने यहां तक आश्वासन दिया था कि बिजली हो जाने पर हर गांव में हर टोले में छोटे छोटे उद्योग का इन्तजाम करेंगे । हम सरकार से जानना चाहते हैं कि कितने उद्योग हमारे यहां खोले गये ? ऐसे तो अभी तृतीय पंचवर्षीय योजना में सारे हिन्दुस्तान का कारखाना हमारे सिंहभूम जिले में लाद दिया गया है । रांची में हेव्ही इंडस्ट्री आपने खोल दिया लेकिन इस योजना के चलते जिनकी जमीन आपने ली उनके बाल-बच्चों के लिये आपने क्या किया और क्या कर रहे हैं ? जिनसे जमीन ली गयी उनसे कहा गया कि जमीन देंगे, लड़कों को पढ़ावेंगे, उनके लिये टेकनिकल स्कूल खोलेंगे और उसमें ट्रेनिंग देकर कार-खाने में ले लेंगे । लेकिन आजतक एक लड़का भी नहीं लिया गया । जिनकी जमीन ली गयी है उनके घर से उनको निकाल दिया गया है और नौकरी से भी उनको बर्खास्त कर दिया गया है । योजना होती है, लेकिन हमपर भी ख्याल करना चाहिये या नहीं तो हमको खतम कर दीजिये ; या तो योजना को चलाया जाय या वहां के बाशिन्दों को खतम कर दिया जाय । क्या सरकार की यही नीति है ? फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना में नहर और तालाब बनाने का स्कीम है । पहली और दूसरी योजना में तारला और रोरों में जो स्कीम चला वह आजतक अधूरी रह गया और रोरा नदी पर जो लाखों और करोड़ों रुपया खर्च किया गया वह काम नहीं हो सका । हमने डिस्ट्रिक्ट डेव्हलप-मेंट कमिटी में इसको कहा । जिलाधीश को खबर दिया गया । हम चाहते हैं कि काम हो लेकिन क्यों ऐसा होता है ? हमलोग जो सुझाव देते हैं उनको नहीं माना जाता है । एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जितनी योजनाएं बनीं वे सब बेकार हैं । स्कीम इस तरह बनाया जाता है, जमीन है ऊंचे पर और पानी नीचे और सर्टिफिकेट केस दायर कर दिया गया । सभापति महोदय, हम और क्या आशा रखें ? यह तो हमने अपनी आंखों से देखा है ? हमारे डिप्टी मिनिस्टर कई दफा गये और इसको देखे भी । हम-लोगों ने सुझाव दिया लेकिन आजतक वह काम नहीं हो पाया है । सभापति जी, आप जानते हैं कि छोटानागपुर और संथाल परगना पहाड़ी इलाका है । उत्तर बिहार समतल है । वहां ऊपर से छोटे-छोटे नाले, झरने बहकर आते हैं और उसीका ठीक तरह से स्थानीय लोगों से पूछकर सिंचाई की व्यवस्था की जाय तो लोगों का बहुत उपकार हो सकता है । उत्तर बिहार में अगर उसी तरह के काम के लिये करोड़ों रुपया खर्च करेंगे तो हमारे छोटानागपुर में वह काम सिर्फ पचास हजार में हो जायगा । हमारे

यहां ब्रह्मचारी मुंडा ने जो प्राजेक्ट बनाया और वह भी एक, दो हजार रुपया खर्च हुआ वह कैसा अच्छा बना जिसको आपके इंजीनियर देखते रह गये। चीफ इंजीनियर को भी सिंचाई के संबंध में कहा गया। ऊपर जहां पचीस मील की सिंचाई हो सकती है उसको छोड़कर नीचे जहां पन्द्रह मील की सिंचाई होगी उसका सर्वे करते हैं। यह तो हमारे इंजीनियर बहादुरों का काम है? आज भी इस साल काम होने जा रहा है, लेकिन उसी तरह हो रहा है सभापति महोदय, यह हमारा कहना है कि छोटे-छोटे कारखाने, उद्योग आप खोलिये और ठीक से हमारे कृषि योजना को लागू कीजिये। यही कहकर मैं समाप्त करता हूं।

श्री लहटन चौधरी—सभापति जी, यों तो मैं कोशिश करूंगा कि दस मिनट में ही

समाप्त कर दूं लेकिन पन्द्रह वर्ष की योजना है तो कम से कम पन्द्रह मिनट रहना चाहिये।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल)—नहीं दस मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिये।

श्री लहटन चौधरी—सभापति जी, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है वह

खासी बड़ी है और यह संतोष की बात है कि पहली और द्वितीय योजनाओं को मिलाकर जो रकम खर्च हुई उससे भी ३४ परसेंट ज्यादा पैसा इस योजना पर खर्च होगा।

यह एक बहुत संतोष का विषय है और साथ ही साथ यह भी संतोष का विषय है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में रेवेन्यु एक्सपेन्डीचर और कैपिटल एक्सपेन्डीचर का रेशियो काफी अच्छी है। करीब २/३ और १/३ का रेशियो है। इसमें काफी आगे बढ़ने का साधन रखा गया है। इसमें शक नहीं है। लेकिन सभापति जी, इस प्लान के अन्तर्गत जो धाराएं हैं, उससे भारी शंका होती है। इसमें "इफ्स और बट्स" रखकर यही साबित होता है कि हमारी योजनाएं उचित ढंग से आगे नहीं बढ़ सकती हैं। इसमें स्वतः ये बातें उठायी गयी हैं। दो-तीन बाधाएं हैं। एक तो यह है कि जो भी टैक्सेज अभी चालू हैं उनसे उनको पैसे आने की संभावना में शक है, हो सकता है पूरा पैसा नहीं आवे। दूसरी बाधा यह है कि नये टैक्सेज सरकार लगाना चाहती है उन सबों को ठीक से वसूली होगी या नहीं, इसको भी बहुत बड़ा शक है। सूखा और बाढ़ की समस्या के कारण लैन्ड रेवेन्यु की वसूली में दिक्कत हो सकती है। तीसरी चीज इसमें यह है कि थर्ड प्लान के लिये २५ करोड़ रुपये नये टैक्सेशन के द्वारा लैंड रेवन्यु से सरकार लेना चाहती है। मैं समझता हूं कि प्लान अच्छा है, इसे कार्यान्वित किया जाना चाहिये। अभी सरकार को बहुत से रुपयों वसूल नहीं होते हैं। कमर्शियल टैक्सेज की वसूली न तो अफसर ध्यान देकर करते हैं और न टैक्स देने वाले ही इसे देना चाहते हैं। इसलिये वे आमदनी को छिपाते हैं। अगर सरकार कमर्शियल टैक्सों की वसूली सख्ती से करे तो नये टैक्सों के लगाने की जरूरत सरकार को नहीं होगी। और न इनका रोना रोते रहना ही पड़ेगा। लैंड रेवेन्यु के बढ़ाने का जो प्रश्न है वह किस ढंग से बढ़ाया जायगा इसकी चर्चा इसमें नहीं है। संभव है सरकार मालगुजारी बढ़ाना चाहती है। जब टैक्स लगाने की बात कीजिये तो पहले इस चीज को देखिये कि जिन लोगों से आप टैक्स लेना चाहते हैं उनकी कमर मजबूत है या नहीं। अगर अधिक जमीन वाले लोगों से मालगुजारी बढ़ा कर लेने की बात करते हैं, तो उनसे वसूली में सरकार को आसानी होगी लेकिन जो लोग कम जमीन वाले हैं जैसे २, ३, ४ एकड़ वाले लोग हैं, अगर उनकी मालगुजारी में वृद्धि करते हैं तो उनसे रुपये वसूल नहीं हो सकते हैं।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल)—एनहान्समेंट ऑफ रेन्ट की बात इसमें कहां आप कर रहे हैं ?

श्री लहटन चौधरी—इसमें २५ करोड़ रुपये लैंड रेवन्यु से लेने की बात है। एग्रीकल्चरल प्रोडियुस की बहुत कमी है, वह चाहे फुड क्रॉप हो या मनी क्रॉप, दोनों की कमी है। तीस वर्षों में १९२१ से १९५१ तक यहां का आबादी ३८ परसेन्ट बढ़ी है और नयी जमीन में एक्सटेन्सिव खेती सिर्फ लगभग ४ परसेंट बढ़ी है।

इसके लिये दो ही तरीके हो सकते हैं, एक तो आप खेतीबारी को बढ़ाने के लिये इन्टेंसिव या एक्सटेन्सिव खेती करें जिसमें फूडक्रोप या मनीक्रोप पैदा हो। अब जब इन्टेन्सिव खेती की बात करते हैं तो उसके लिये सबसे बड़ी चीज सिंचाई की जरूरत है। मैं इस बात को मानता हूं कि इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से सिंचाई के लिये ज्यादे रुपये रखे गये हैं लेकिन फिर भी वे अपर्याप्त हैं। इसके एक-ो उदाहरण में आपके सामने रख देना चाहता हूं। सिंचाई की बहुत-सी योजना, छोटी और बड़ी बनी है, जिनको द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ही समाप्त करने की बात थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाप्त भी हो गयी लेकिन सिंचाई की बहुत सी स्कीम अभी अधूरी रह गयी हैं। जो बहुत बड़ी योजना हो उसमें कुछ समय लग सकता है और उसके लिये ५ या १० वर्ष का समय लग सकता है। लेकिन जो छोटी-छोटी स्कीम हैं उनमें अभी जो ५ वर्ष या उससे ज्यादा समय लगता है वह मेरे जानते ठीक नहीं है। हमारे माननीय सदस्य श्री राधानन्दन झा ने यह कहा था कि कोसी में वेस्टर्न कैनल और इस्टर्न कैनल सिस्टम हैं जिसमें वेस्टर्न पर १२ करोड़ और इस्टर्न कैनल पर ५ करोड़ पये खर्च होनेवाले हैं। लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि १२ करोड़ में सिर्फ २ करोड़ और इस्टर्न कैनल के लिये जो ५ करोड़ का प्रोविजन है उसमें २॥ करोड़ रूपये खर्च करने की बात इस तृतीय योजना में है। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वेस्टर्न कैनल के लिये सारा एस्टाब्लिशमेंट है, आपके इंजीनियर्स हैं, ओवरसियर्स हैं और दूस े स्टाफ हैं और उनसे आप काम ले सकते हैं। आपके पास मैनपावर भी है और यदि आप चाहे तो दो वर्ष में इस काम को समाप्त कर सकते हैं लेकिन फिर भी ऐसा न करके उसमें काफी विलम्ब हो रहा है और मेरे जानते ऐसा करना उचित नहीं है। आप फाइनेंस का भी सवाल उठा सकते हैं। इसके संबंध में मैं यह कह सकता हूं कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट के लिये आपने ४० करोड़ रूपये का प्रोविजन किया है और इसमें से करीब ३० करोड़ रुपया आप इस काम पर खर्च कर सकते हैं।

श्री नन्द किशोर सिंह—क्या सदन में कोई सदस्य चेयर की तरफ पीठ करके बैठ सकता है ?

Shri MOHAMMAD SHAHAJEHAN : I am very sorry Sir,

श्री लहटन चौधरी—मेरे ख्याल से कम्युनिटी प्रोजेक्ट का जो काम हो रहा है उसमें बहुत सा वेस्टेज होता है। इसको बन्द करने के लिये तो नहीं कह सकता क्योंकि वहां पर भी कुछ अच्छे काम हो रहे हैं लेकिन नये ब्लौक के खुलने के पहले जो १ या १॥ लाख का मकान बनता है उसको अभी बन्द किया जा सकता है और स्टाफ को भाड़े

के मकान में रख कर इसका रुपया सिंचाई के मद में अभी खर्च किया जा सकता है। इससे करोड़ों रुपया आपको मिल सकता है।

मैं आपसे आग्रह करूंगा कि १॥ लाख रुपये बचाने के लिये अगर दो-चार मकान भाड़ा पर लेना पड़े और उससे काम चल जाय तो उसे आप ले लें। अगर आप इतने रुपये निकाल सकें तो मजे में आपका इरिगेशन का काम चल सकता है। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि पहले मकान बनेगा और उसके बाद ही पैखाने के लिये गढ़ा खुदायगा और इससे काम चलने को नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप सिरियस होकर रुपये निकालना चाहते हैं और इरिगेशन का काम चले तो, आपको इसमें करटेलमेंट करना पड़ेगा। अगर मकान में कुछ जकमी कर सकें और फो ब्लोक से दो लाख रुपये बचा सकें तो आपको १०-१२ लाख रुपये की बचत हो जायेगी और इस काम को कर सकते हैं।

दूसरी बात मैं रोड के संबंध में कहना चाहता हूं। जहां तक रोड की बात है, रोड के डेवलपमेंट के लिये काम करना अनिवार्य है, जिससे खेती-बारी और दूसरे-दूसरे काम चल सकें। आपलोगों ने पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट नागपुर प्लैन की इसके संबंध में उपेक्षा कर रही है। इस योजना को पूरा करने के लिये ३२ लाख रुपये तृतीय योजना में खर्च होने जा रहे हैं लेकिन इतने रुपये से रोड के डेवलपमेंट का काम पूरा नहीं होगा। जहां तक सहरसा जिले में रोड की बात है, पॉपुलेशन के हिसाब से ३॥ हजार मील में सड़क होनी चाहिये पर वहां ८०० मील ही सड़क है। जिले के हिसाब से भी ४५० मील में रोड होनी चाहिये पर १६६ मील ही रोड लिया गया है। मैं इस बात को मानता हूं कि पहले आप कोसी के चलते वहां पर बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते थे पर अब जब कोसी में बांध हो जाने की वजह से और जिलों की भांति ही वहां पर सड़क का काम करने की कोशिश करनी चाहिये लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना में द्वितीय योजना से भी कम रुपये रखे गये हैं। आप इस दिक्कत को तृतीय योजना में पूरा कर सकते थे और इसको पूरा किया जाना भी चाहिये। इसलिये सभापति महोदय, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि सरकार मेरी बातों पर सोचे और इसको कार्यान्वित करें।

*श्री कामदेव प्रसाद सिंह—सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान तृतीय

पंचवर्षीय योजना के भोजूम २, पेज १६६ की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें अजय नदी पर अजय वैली स्कीम बनायी जाने वाली है। बहुत से माननीय सदस्यों ने छोटानागपुर और संथाल परगना के सम्बन्ध में सदन का ध्यान दिलाया है, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। फर्स्ट सेकेन्ड फाइव-इयर प्लान में छोटानागपुर और संथाल परगना के लिए जो माइनर इरिगेशन के लिए स्कीम बनी, सिंचाई के लिए वह असफल रही। मेरी आशा और विश्वास है कि छोटानागपुर और संथाल परगना में जो छोटी छोटी नदियां बहती हैं उनसे अगर सिंचाई की व्यवस्था की जाय तो सिंचाई का काम चल सकता है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं हो रहा है। आज तक जितनी भी स्कीम्स वहां के लिये बनीं उनमें से ज्यादा भाग रुपये का सरेन्डर हो गया। कारण सरेन्डर का यह बताया गया कि इंजीनियर की कमी है। मध्यम सिंचाई योजना की अगर व्यवस्था की जाती तो छोटानागपुर और संथाल परगना की खेती की तरक्की हो सकती थी, लेकिन यह भी नहीं हुआ। माइनर इरिगेशन के लिए दो हजार रुपये में एक कुआं बन सकता है और उससे एक एकड़ जमीन को सिंचाई हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तृतीय योजना में भी इसकी ओर कोई इशारा नहीं है। मैं आपसे

5/10/61

बराबर ही कहता हूं और माननीय सदस्य भी कहते हैं कि छोटानागपुर और संथाल परगना का हिस्सा बिहार का दक्षिणी हिस्सा है और मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि डी० वी० सी० बना तो संथाल परगना जिले की छाती पर बना मयूराक्षी डैम बना तो संथालपरगना की छाती पर ही बना, पर आपने सुना होगा कि इस डैम से संथाल परगना जिले में जमीन की पटवन नहीं हो सकती है। हो सकता है कि दो-चार हजार एकड़ जमीन में सिचाई होती हो लेकिन पूरी सिचाई इससे नहीं हो रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इन योजनाओं के चलते सैकड़ों गांव डूब गए, बंगाल का प्रोटेक्शन करने के लिए वहां के लोग बरबाद हो रहे हैं पर फायदा नहीं हो रहा है। आपने तृतीय योजना में कहा है कि वहां एक डैम का निर्माण होने जा रहा है जिसका नाम है अजय रीवरवैली स्कीम। तृतीय योजना के पेज १६६ में है :

"*Ajoy Valley Barrage* (*Santhal Parganas*).—The Scheme is a part of the bigger scheme known as Unified development of Ajoy Valley which consists of six dams and one barrage. The present scheme consists of a barrage at the confluence of Jainty and Ajoy at village Siktia in Santhal Parganas district. The scheme on completion will benefit 90,000 acres and will cost Rs. 300 lakhs."

मेरा कहना है कि जहां यह स्कीम बनने जा रही है उसमें मेरे क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग पड़ जाता है और वह डूब जायेगा। मैंने प्रश्न के द्वारा यह जानने की कोशिश की थी कि कितनी जमीन इससे डूबेगी, पर जवाब नहीं मिला। वोलूम २ में दिया हुआ है कि ९० हजार एकड़ जमीन की इससे पटवन होगी, पर कितनी डूबेगी, यह नहीं दिया गया है। मैंने व्योरेवार इसके बारे में डिटेल जानना चाहा था, पर नहीं मिला। मैंने इसको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिटी में रखा था और कहा था कि बंगाल को बचाने के लिए हमलोगों को क्यों दबांचो बनाया जा रहा है और हमलोगों को डूबाया जा रहा है, पर कोई आश्वासन नहीं मिला। इसलिए मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। अगर हमको यह आश्वासन मिले कि इससे आपलोगों का उपकार होगा तो ठीक है नहीं तो मैं इसका विरोध करता हूं। मेरा कहना है कि बंगाल का प्रोटेक्शन करने के लिए हमलोगों को दबांचो बनाया जा रहा है और डुबाया जा रहा है।

हमारे यहां आदमी बस नहीं रहे हैं और भिन्न-भिन्न लोग बाहर से आते हैं, जमीन लेते हैं, केस भी करते हैं और बिजली भी ले जा रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि प्लान नहीं बने और अन्य जगहों की तरक्की नहीं हो लेकिन यहां आप ध्यान नहीं देते यह उचित नहीं है। खुशी की बात है कि हमारे मुख्य मंत्री देवघर के हैं लेकिन न जाने क्यों वे सोये हुये हैं और हमारे जिले की तरफ उतना उनका ध्यान नहीं है। उनके चीफ मिनिस्टर होने पर हमें जो खुशी हुई थी वह अब दुख में परिणत हो रही है। धान मर रहा है, लोग पत्ते खाकर, जंगल का महुआ खाकर गुजारा कर रहे हैं लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जाता। तीसरी योजना में भी ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आती और न कोई प्रबंध मालूम होता है जिससे हमारे यहां सिचाई हो सके और खेतों का पटवन हो।

इसके बाद मैं आपका ध्यान प्लान एस्टीमेट के पेज ४ पर टेबुल नं० २ की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें यह दिया हुआ है कि नेट एरिया कल्टिवेटेड १९२१ में ७२ परसेंट और १९५१ में ५५ परसेंट था। नेट एरिया इरीगेटेड १९२१ में १४ और १९५१ में १३ परसेंट। डबल-क्रौप्ड एरिया का फीगर १९२१ में १९ और १९५१ में १६ परसेंट है। यह फीगर बतलाता है कि १९२१ से १९५१ में डिक्रीज होता गया है।

इसके बाद उसी जगह पेज ५ की ओर में आपका ध्यान खींचना चाहता हूं जहां आइटम १२ में यह लिखा हुआ है कि :

"It has already been stated that according to the census of 1951, 86 per cent of the population of Bihar were dependent on agriculture."

फिर नीचे टेकनो-इकौनौमिक सर्वे रिपोर्ट के बारे में है कि :

'To sum up ' in the words of the Techno-Economic Survey, over the years there has been a general deterioration in the economic conditions of the people, increase in populationpressure, increase in dependance on agriculture, decreasing availability of land and its resources, and diminished opportunities for migration."

तो पहली और दूसरी योजना में इकोनोमिक प्रेशर ज्यादा हुआ है और लोगों की आमदनी घटी है और यह दुख-द' अभी जारी है ।

इसके बाद में आपका ध्यान पेज ६० की ओर ले जाना चाहता हूं जहां पर कैपिटा इंकम के बारे में लिखा है कि :

"Hence although at present it is not possible to forecast the rise in percapita income in the State, it is hoped that data in this regard would be available during the Third Plan."

इतने रुपये खर्च हुये लेकिन सरकार के पास डाटा नहीं है कि पर कैपिटा इंकम को देश में तरक्की हुई है या घाटा हुआ है और इसका अंदाज थर्ड फाइव-इयर प्लान में किया जायेगा । इसलिये मैं समझता हूं कि यह प्लान अंधेरे का प्लान है। रुपया आप खर्च कर रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं हो रहा है और न कोई फायदा है ।

अनइम्पलायमेंट की बात कहते हैं । कितने आदमियों का इम्पलायमेंट होगा यह इससे साफ नहीं मालूम होता है इसलिए मेरा कहना है कि थर्ड फाइव इयर प्लान में जो भी आउटपुट का अन्दाजा करते हैं वह सब हवावाली बात है।

प्लान का निर्माण उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दोनों के लिए एक सा किया गया है हालांकि दोनों के अलग अलग प्रोबलेम है । उत्तर बिहार की मिट्टी दूसरी है, वहां इरिगेशन के साधन कुछ और हैं और दक्षिण बिहार में कुछ और ही साधन है। दोनों को एक साथ मिला करके निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए । १५० रुपए प्रति एकड़ तक बैठेगा तो माइनर इरिगेशन में लिया जाता है और इससे बढ़ने पर वह मीडियम इरिगेशन में चला जाता है, उसे इंजीनियर नामंजूर करके भेज देता है कि माइनर इरिगेशन में नहीं आता है । हैदराबाद में पहाड़ी इलाकों में तरक्की हुई है और वहां दोफसला धान होता है । जमशेदपुर और अन्य जगहों से आप टैक्स लेते है । हमारे यहां माइन्स हैं कोयले के, अबरख के जिससे देश भर का काम चलता है उसको आप उर्वरा नहीं बना सकते हैं तो मैं कहूंगा कि दक्षिण बिहार के लिए प्लान को कोई आवश्यकता नहीं है, उसी आमदनी से हम अपने पैरों पर खड़े हो जायंगे ।

दूसरी बात सड़कों के बारे में है। नागपुर कांग्रेस में १०,२११ माइल सड़क बनाने का निश्चय हुआ था लेकिन दूसरी योजना में सिर्फ ८ हजार माइल ही बन सकी है ।

युनिवर्सिटी एडुकेशन के बारे में पेज २६ में एक टेबुल है उसमें दिया हुआ है कि पटना, बिहार, रांची और भागलपुर में क्रमश: ३४, १३, ११, ६ डिपार्टमेंट्स हैं ।

जेनरल एडुकेशन में ५, १, १, १ और प्रोफेशनल एंड टेकनिकल एडुकेशन में ६ और सब जगह जिला जेनरल एडुकेशन को छोड़ करके युनिवर्सिटी जो अभी शैशवावस्था में है उसमें भागलपुर में न मेडिकल का इन्तजाम है, न इंजीनियरिंग का इन्तजाम है वहां के लड़कों के पढ़ने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। हमारा इलाका हमारे जिले में भी सब से ज्यादे पिछड़ा हुआ है इसलिए मैं चाहता हूं कि इन सब बातों को ओर सरकार का ध्यान जाय।

हमारे यहां जो साक्चो डेम हो रहा है वह हमारे इलाके को डुबाने के लिए किया जा रहा है। इससे हमलोगों को कोई फायदा नहीं है इसलिए मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जवार हुसैन—आज चार से पांच कर दिया गया है। दशहरे को छुट्टी का ख्याल

करते हुए ११ तारीख को ९ बजे से १ बजे तक हमलोग समय ले सकते हैं। इस प्रोग्राम के मुताबिक ३ घन्टा समय उस दिन मिल जायगा।

श्री बद्री सिंह—इसकी महत्ता को देखते हुए मैं समझता हूं कि ठाकुर जी के

अनुसार समय बढ़ाना जरूरी है। अगर ज्यादा समय नहीं बढ़ाया गया तो भिन्न-भिन्न सदस्य अपना विचार प्रकट नहीं कर सकेंगे इसलिए जो ठाकुर जी ने सुझाव दिया है उसीके मुताबिक बढ़ाया जाय।

श्री जवार हुसेन—श्री कर्पूरी ठाकुर ने ६ घन्टे के समय की मांग की थी, उस दिन

---

३ घन्टा मिला और एक घन्टा आज मिल ही गया इसलिए अब प्रेस नहीं करना चाहिए।

*श्री महावीर राउत—सभापति महोदय, यह पुस्तिका हमलोगों के बीच बटी है और

हमलोगों ने से पढ़ा भी है। इससे हमलोगों को बहुत बड़ी आशा बंधी है लेकिन साथ ही साथ कहना है कि हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है और खास कर बिहार तो कृषि प्रधान प्रांत ही है। ईख का फसल हमलोगों के यहां प्रधान फसल मानी जाती है। हमारे यहां २८, २९ शगर मिल है। आज हमने पेपर में स्टेटमेंट पढ़ा तो देखा कि केन्द्रीय सरकार ने एक आर्डिनेंस किया है कि पहली नवम्बर से १० परसेंट कम शूगरकेन कटेगा और किसानों से कहा जायगा कि जो दस परसेंट कम होगा उसको क्रशिंग के लिए वे स्वयं व्यवस्था करें। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि इससे दिहातों में हाहाकार मचेगा। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इसे किया है पहली नवम्बर से और उसी वक्त से फैक्ट्री भी खुलेगी। इसमें है कि :

"The Union Government has promulgated an Ordinance taking power to fix from time to time the quantity of sugar which may be produced in a factory during a year. It will come into effect from November 1."

उसी वक्त फैक्ट्री खुलेगी और हमलोग ईख पैदा भी कर चुके हैं। दो महीने में फैक्ट्री को ईख देना है ऐसे समय में आप कहते हैं कि द परसेंट कम लिया जायगा और अगर उससे ज्यादे फैक्ट्री लेगी तो उसपर स्पेशल एक्साइज डियूटी लगेगी। इससे आफत आनेवाली है, किसानो में हाहाकार मचनेवाला है इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी श्री चन्द्रशेखर सिंह जो अच्छे नवयुवक हैं उनसे आग्रह करता हूं और इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर से भी आग्रह करता हूं कि वे इस

पर सोंचे कि दस परसेंट कम होगा तो गरीब किसानों पर पहली नवम्बर से क्या असर होगा।

सरकार को ऐसा काम करना चाहिये जिससे किसानों की हालत खराब नहीं हो। ईख तैयार हो रही है, इसलिये सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये इससे जो भीषण समस्या उठनेवाली है वह नहीं उठे। सरकार समय रहते सचेस्ट हो जाय।

अब मैं यातायात पर आता हूं। दरभंगा जिले की जनसंख्या सभी जिलों से अधिक है, आजकल ४३ लाख हो गयी है। १९४३ में सभी राज्यों के चीफ इंजिनियरों की बैठक हुई थी। उसमें यह कहा गया है :

" In North Bihar the development of roads to link the different areas is a long felt need ; and in South Bihar and Chotanagpur, roads have to be developed as they are the arteries of transport in the industrial region. A conference was held in 1943 at Nagpur of Chief Engineers of Provinces and others interested in the development of roads ; this conference evolved certain principles for development of roads taking into account such factors as population."

हमारे यहां सड़कों की हालत बहुत खराव है। पहली पंचवर्षीय योजना में बहुत कम सड़कें वनी हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि हमारे यहां की डेवलपमेंट कमिटी से जिन सड़कों का नाम आवे सरकार उसे प्रायरिटी देकर काम शुरू कर दे। सरकार ने निश्चय किया था कि अंचल हेडक्वार्टर, सबडिवीजनल हेडक्वटंर और थाना हेडक्वार्टर को मिला दिया जायगा। इस काम क शीघ्र किया जाय।

दरभंगा जिले में ४३० मील रेलवे लाइन चाहिये, जनसंख्या के हिसाब से। किन्तु अभी केवल १२० मील रेलवे लाइन है। बाकी ३१० मील और रेलवे लाइन चाहिये। यह विषय केन्द्रीय सरकार का है लेकिन हमारी सरकार को चाहिये कि वह केन्द्रीय सरकार से इस बात की सिफारिश करे कि सकरी से हसनपुर और हसनपुर से बरौनी तक रेलवे लाइन शीघ्र बिछा दे। यह ८० मील से अधिक नहीं है। रेलवे लाइन होने से लोगों को अधिक काम मिलेगा, काम बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और लोग खूब खायेंगे। मोकामा पर जो पुल बना है उससे हमलोगों को भी लाभ उठाने का मौका दीजिये।

दरभंगा में संस्कृत विश्वविद्यालय खुल रहा है। दरभंगा महाराज ने उस भवन को दान कर दिया है जिसमें महारानी साहिबा रहती थीं। वहां मंडन मिश्र तथा दूसरे बड़े-बड़े विद्वान हो गये हैं। दरभंगा महाराज की राज्यपाल महोदय से बातचीत हुई थी उसमें उन्होंने इस मकान के बारे में कहा है :

"The Principality of Tirhut was given to my ancestor, Mahamahopadhyay Maharaja Mahesh Thakur, by the Great Emperor Akbar, just four hundred years ago in appreciation of his learning in Sanskrit."

सभापति (श्री रामनारायण मंडल)—उसमें कितने विद्यार्थी हैं ?

श्री महावीर राउत—सभी मिथिलावासी विद्यार्थी हैं। मैं सरकार से कहना चाहता

हूं कि इसके लिये १५ लाख रुपये जो दिया गया है वह बहुत कम है।

अब मैं पुलिस कमीशन पर आता हूं, आप एफिशिएन्सी चाहते हैं।

लेकिन कमीशन ने इसे रिकोमेंड किया है कि पुलिस को इम्प्रूभ करने के लिये दो करोड़ रुपये की उसने मांग की है। आप दो करोड़ रुपये देने में असमर्थ हैं। इसमें लिखा है कि कांसटेबुल का दरमाहा......

सभापति (श्री रामनारायण मंडल)—आप पे कमीशन का हवाला इसमें न दें।

श्री महावीर राउत—लेकिन जो दरमाहा रखा गया है वह तो कम है।

श्री ललितेश्वर प्रसाद साही—मेरा एक प्वाएन्ट ऑफ इन्फौरमेशन है। जानकारी के लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस विभाग प्लान के अन्दर में नहीं है वह नन-प्लान में आता है।

श्री महावीर राउत—हमको मालूम है कि नन-प्लान करके इसे काट देंगे। फाइनेन्स कमीशन आया था उसमें भी इसकी चर्चा चली थी। अगर आप अच्छा काम देखना चाहते हैं तो उसके लिये पैसा भी खर्च कीजिये।

अब मैं आग्रह करना चाहता हूं कि बैकवर्ड क्लास के लिये काकाकालेलकर आयोग की जो रिपोर्ट है उसे मान लिया जाय।

अन्त में यह कह कर मैं बैठ जाना चाहता हूं कि जिस तरह से पब्लिक कमिशन है उसी तरह से छोटी-छोटी नौकरियों के लिये जूनियर पब्लिक कमीशन हो जिसमें सभी लोग आ सकें। सेक्रेटेरियट म जिनकी पैरवी होती है उन्हीं को नौकरी मिल पाती है। इसलिये जूनियर पब्लिक कमीशन सरकार को अवश्य बनाना चाहिये।

श्री हरिचरण सोय—माननीय सभापति जी, इस थर्ड फाइव-इयर प्लान का जो एपरोच है उसकी ओर संकेत करते हुए एक चीज कही गयी है कि इसके अन्य आदेशों में एक यह भी है कि लेस प्रिविलेज्ड क्लास को बेटर अपोर्चुनिटीज मिले और उनमें जो तरक्की की कमी हुई है वह जल्द पूरी हो जायेगी। सभापति जी, इस ओर विचार करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इस चीज को सही मानता हूं कि हमारे राज्य में दो मोटा-मोटी हिस्से हैं, एक ओर एग्रीकलचर है और दूसरी ओर इन्डस्ट्रीज एरिया है। यह विशेष लोगों का हमारे राज्य के सरकार के नेताओं का, और और लोगों का यह सोचना है कि खेती के लिये अधिक तरक्की उत्तर विहार के इलाकों में करना है। मगर इस प्लान को बनाते हुए यह भूल जाते हैं कि हमारे सामने प्रश्न क्या है? हमारे राज्य में फूड का हमेशा प्रब्लेम डिफिसिट रहा है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरी होने पर भी हम आशा करते हैं कि फूड सरप्लस होगा। लेकिन यह तो मेरी आशा है। उत्तर विहार में कितना भी डेवलपमेंट करें, वह इस स्थिति में नहीं होगा कि सरप्लस फूड और खाने की व्यवस्था कर सके। स्थिति यह है कि दक्षिण विहार को खाने-पीने की व्यवस्था अपने ही करनी होगी। तो मैं यह कहूंगा कि इरिगेशन के मामले में जो व्यवस्था की गयी है दक्षिण विहार में वह ठीक नहीं है। सरकार दक्षिण विहार में खेती की तरफ नहीं बल्कि इंडस्ट्रीज की तरफ ज्यादा महत्व देती है। इसका नतीजा हुआ है कि सेकेन्ड प्लैन में होल इरिगेशन बजट में लेस दैन १० परसेंट खर्च किया गया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में सारे इरिगेशन बजट में लेस दैन ६ परसेंट खर्च करना है। ऐसा करना सरासर बेइन्साफ है। एक तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की मांग है और दूसरा एफोरेस्टेशन

करने की मांग है। इससे होता क्या है। आलरेडी दक्षिण बिहार डेफिसिट एरिया है और ऐसा करने से डेफिसिट और बढ़ेगी। और आज की बढ़ती हुई आबादी, और उद्योग धन्धे के कारण जितनी जरूरत खाद्यान्न की होगी उसको आप पूरा नहीं कर सकेंगे। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वह बड़ी-बड़ी स्कीमों को न लेकर छोटी-छोटी स्कीमों को लागू करे ताकि लोगों को फायदा हो। हिसाब लगाकर देखा है कि हमारे छोटानागपुर में दस इरिगेशन की स्कीम है उसको चालू करने से लोगों को फ़ायदा हो सकता है लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसपर सरकार ध्यान नहीं देती है। जो स्कीम पहली योजना में थी वही स्कीम दूसरी योजना में भी दिखायी गयी है। और तीसरी योजना जो बनी है उसमें भी वही सारी स्कीम हैं। एक स्कीम हमारे जिले में सोना रीभर है जो पहली योजना के समय से चली आ रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जो लॉंग रेन्ज प्लैन करती है उसमें दक्षिण बिहार में इरिगेशन की जरूरत है और उसका इंतजाम होना चाहिये।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के डिप्टी मिनिस्टर ने भी कहा है कि वहां बड़े-बड़े उद्योगों की व्यवस्था होने पर भी वहां के लोगों को परमानेंट इम्प्लायमेंट नहीं मिलता है। थोड़ा-बहुत टेम्पोरेरी इम्प्लायमेंट मिल जाता है। हटिया में लोगों को परमानेंट इम्प्लायमेंट नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वहां छोटे-छोटे उद्योगों का इंतजाम होना चाहिए। विशेष कर काटेज इंडस्ट्रीज का, ताकि लोगों को काम मिल सके। लेकिन सरकार काटेज इंडस्ट्रीज पर उतना ध्यान नहीं देती है जितना बड़ी इंडस्ट्रीज पर। हमलोग कई साल से सरकार का ध्यान इस ओर खींचते रहे हैं कि उस इलाके में काफी मात्रा में कच्चा माल मिल सकता है। बांस और सबई घास मिल सकती है जिससे छोटे-छोटे कई काम हो सकते हैं। लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है।

तसर की ओर इस योजना में व्यवस्था की गयी है लेकिन वह बहुत कम। सिर्फ कुछ लोगों को नौकरी देने के लिए इसकी व्यवस्था की गयी है। उसका स्कोप अधिक नहीं है। इसलिए इसकी अधिक व्यवस्था होनी चाहिए।

तीसरी योजना में यह भी कहा गया है कि संविधान के आर्टिकल ४६ में और ५ वें शेड्यूल में कहा गया है और साथ ही साथ जितने कमिश्नर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के हैं उन्होंने कहा है कि इसके लिए जो अलग-अलग व्यवस्था है वह खत्म होनी चाहिए लेकिन हमको देखना यह है कि पहली और दूसरी योजना में इसके लिए सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या किया है। वेलफेयर डिपार्टमेंट में जितने खर्च की व्यवस्था की गयी है उसको देखने से पता चलता है कि सरकार ने इस ओर उतना ध्यान नहीं दिया है जितना देना चाहिए। मैं आपका ध्यान थर्ड फाइव-इयर प्लान के पेज २७३ में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के कमिश्नर ने अपनी पहली रिपोर्ट जो १९५१ में दी थी वह इस प्रकार है :

"The general underlying spirit of all safeguards for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes embodied in the Constitution is that with a period of ten years from the commencement of the Constitution, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the weaker sections of the people, socially and educationally backward classes of citizens who should be protected from social injustices and all forms of exploitation and whose educational and economic interests should be protected, should be brought in line with others

so that after the period of ten years they may stand on their nwo legs without the help of crutches in the form of safeguards."

तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप जो रिजर्वेशन दस वर्ष के अन्दर खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी क्या योजना है ? क्या आपने तृतीय योजना बनाते वक्त इस कमिश्नर की रिपोर्ट को सामने रखा था ? मेरा कहना है कि इसके आधार सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हू कि संविधान में भी और बैकवर्ड क्लास की कमिश्नर की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि सबलोगों की प्राइमरी शिक्षा उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए। तो क्या आप दूसरी योजना की समाप्ति मी इस काम को कर सके है या तीसरी योजना शुरू होने तक कर सकेंगे। मैं कहूंगा कि रशिया में जहां छोटे छोटे प्रदेश हैं और जिनकी आबादी एक लाख है और जिनकी अपनी लिपि नहीं है, वहां इसकी व्यवस्था है लेकिन वर्तमान सरकार ने ऐसा नहीं किया और केवल स्क्रीप्ट के नाम पर टैक्स बुक बनाने के लिए इस तरह का बहाना किया है।

आपका ध्यान कलचरल और साहित्यिक उन्नति की ओर गया है इससे हमको खुशी है। जहां संस्कृत और जंग्रालोजी के लिये आपने ४४ लाख रुपया रखा है वहां अरबी तथा परशियन के लिये सिर्फ ८ लाख रखा है। संविधान के अनुसार यह जरूरी है कि शिक्षा मदर टंग में दी जाय लेकिन इस ओर सरकार कोई कदम नहीं बढ़ा रही है और इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है।

अब मैं वेलफेयर स्कीम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सरकार ने यह स्वीकार किया है कि सेकेन्ड प्लान में जितना रुपया इस मद में खर्च किया उतना काम नहीं हुआ और करीब १ करोड़ ५० लाख रुपया सरेन्डर कर दिया गया और उसपर भी मजा यह है कि इस्टैब्लिशमेंट पर करीब ७० लाख रुपया खर्च हुआ और असली काम पर कम खर्च हुआ। वेलफेयर के काम में कैसे लोगों को रखा जाय उसके संबन्ध में बैकवर्ड क्लासेज कमीशन तथा और लोगों ने भी कहा है कि सबसे जरुरी चीज है कि जिन लोगों से यह काम लिया जाय उनकी ट्रेनिंग ठीक ढंग से होनी चाहिये। इसलिये इतना ही जरुरी नहीं है कि उनको रांची के ट्राइबल ट्रेनिंग इंसटीट्यूट में कुछ दिनों के लिये भेज दिया जाय। जरूरत इस बात की है कि वे जिनके बीच काम करेंगे उनके कलचर, कस्टम और रस्म-रिवाज से अच्छी तरह वे परिचित हो जांय। मैं तो सरकार से कहूंगा कि आप कम खर्च करें लेकिन सही ढंग से खर्च करें ताकि खर्च के अनुपात में लाभ हो सके। सही ढंग से ट्रेनिंग देने की व्यवस्था सरकार करे तो काफी लाभ होगा।

बैकवर्ड कलासेज कमीशन का कहना था कि पिछड़े हुये इलाकों के लिये खास इंतजाम होना चाहिये, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारे मित्र तिवारी जी ने भी कहा कि हरिजन के मामले में सरकार छोटानागपुर के साथ स्टेप-मदरली ट्रटमेंट करती है।

सभापति (श्री रामनारायण मंडल)—आपका समय हो गया, आप अब बैठ जायं।

---

*श्रीमती शांति देवी—सभापति महोदय, तृतीय पंचवर्षीय योजना के सामने सब से बड़ी समस्या खाद्यान्न के उत्पादन की समस्या है। विगत योजनाओं के समय से ही इस समस्या को हल करने के लिये जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर ग्राम पंचायतों की स्थापना कर अभी-अभी सीलिंग बिल पासकर हमलोगों ने भूमिका मात्र तैयार की है। सिर्फ

इतने से ही खाद्यान्न की वृद्धि नहीं हो सकती है विशेषकर पूर्णियां जिले के उत्तर-पूर्व स्थित हमारे पलासी क्षेत्र में जहां की भूमि धान तथा पाट के लिये अत्यन्त उर्वरा है।

जबतक बकरा, कनकई, महानंदा नदियों की बाढ़ से इस क्षेत्र को नहीं बचाया जायगा तबतक उत्पादन में वृद्धि की कोई संभावना नहीं है। इन्हीं नदियों के कारण यातायात के लिये भी अबतक किसी सड़क की व्यवस्था नहीं हो सकी है। जो कच्ची सड़कें बनायी भी जाती हैं प्रतिवर्ष बरसात से कट जाने के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाना भी असंभव-सा हो जाता है। किशनगंज या बहादुरगंज से टेढ़ागाछ तथा दिघलबाक तथा अररिया से पलासी जाना असंभव हो जाता है। अभी जो हमारे प्रान्त से भेजे गये पर्यवेक्षक उम्मीदवारों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये पूर्णिया गये थे बहादुरगंज से आगे टेढ़ागाछ तथा दिघलबाक तथा अररिया से पलासी थाना तक नहीं जा सके। पटुए की खेती इस एलाके में काफी होती है लेकिन सड़क की व्यवस्था नहीं होने के कारण इन इलाकों के लोग गांव के हाट में २० रु० २२ रु० मन पाट बिक्री कर देते हैं जबकि पटुए का भाव किशनगंज तथा अररिया में ३० रु० और ३२ रु० मन रहता है। गरीब किसान कठिन परिश्रम कर उत्पन्न किये हुए चीजों का उचित मूल्य तक नहीं पा सकते हैं। बिहार के थर्ड फाइव-इयर प्लान के भोलूम में सिंचाई तथा फ्लड कंट्रोल संबंधी पन्नों को उलटने से मैं हताश हो जाती हूं कि इस तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में भी कनकई तथा महानंदा को कंट्रोल करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि पूर्णियां के उत्तर-पूर्वीय भाग के ऊपर भी जो नेपाल की तराई से मिला हुआ है सम्यक विचार कर इस क्षेत्र के लोगों के दुख दूर करने की व्यवस्था इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर की जाय।

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद सिंह—मान्यवर सभापति महोदय, यह निर्माण की लीला है और

उत्पादन की वेला है। अगर इन दो चक्कियों में सारा बिहार चलता रहे और चक्की चलानेवाले उत्पादन और निर्माण का ख्याल रखें कि कितना निर्माण होता है और कितना उत्पादन बढ़ता है तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या का मुकाबला करने के लिये ठीक है। वरना आपके माध्यम से मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि जो निर्माण करता है, जो अपने पसीने की कमाई से कोयला को निकालकर सोने की तरह दान करता है क्या उसके लिये एक चुल्लू शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं हो सकती है। हजारीबाग जिले में दो लाख आदमी पतरातू से लेकर बेरमो तक कोयले के खानों में नीचे मेहनत करते रहते हैं लेकिन बाहर निकलने पर उनको एक चुल्लू शुद्ध जल मिलने का इंतजाम नहीं है। १९५८ में डा० श्रीकृष्ण सिंह जब जिन्दा थे तो उनसे मैंने अपने बजट के भाषण में अपील की थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे जल का इंतजाम करेंगे। योजनाएं बनीं लेकिन न जाने कबतक हजारीबाग पहुंचेंगी।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं योजना के विषय में वह यह है कि मैंने डेवलपमेंट कमिटी में रिजोलूशन दिया और सरकार जब इसपर सील दे रही थी तो उस वक्त उस रिजोलूशन को क्यों नहीं देखा? झरिया में ही एक जगह है जहां फर्स्ट क्लास कोयला मिल सकता है और उस कोयले को जो मजदूर अपनी जिन्दगी की बाजी लगाकर, पसीना बहाकर खान से निकालते हैं जिससे बड़ी-बड़ी ट्रेनें चलती हैं, क्या उनको पीने का पानी पाने का अधिकार नहीं है? यह योजना बिलकुल अनडिमोक्रेटिक और डेस्पोटिक है।

दूसरी बात यह है कि कोई देश खेती और उद्योग दोनों को बढ़ाकर ही उन्नति करता है। इसका मिसाल अमेरिका हमारे सामने मौजूद है। खेती के विषय में इस योजना में कुछ ज्यादा रुपया रखा गया है। एक तरफ दामोदर रीवर है और दूसरी तरफ जो नदी है इन दोनों के बीच की खाइयों को बांध देने से सारे गांव के लोग खुशहाल हो जायेंगे। मजदूरी करनेवाले और खेती करनेवाले दोनों ही खुशहाल होंगे। इनकी इंडस्ट्रियल पालिसी का किसी को पता नहीं। मदमस्त हाथी की तरह इनका नेशनल प्रोग्राम चलता है। मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर और प्लानिंग कमीशन से पूछना चाहता हूं कि इस तरह की ढुलमुल नीति से क्या कोई भी जीवन में सफलीभूत हो सकता है ?

दोनों क्षेत्र में विकास के लिये जो जमीन ली जा रही है उसके विषय में यह कहना है कि जिन लोगों को जमीन छीन रहे हैं उनके बसने के लिये जगह नहीं है, उनके बसाने की कोई नीति क्या इनके पास है ?

हजारीबाग जिला में तिलैया डैम बना और भी बहुत-से डैम बनाये गये लेकिन वहां एक लुटिया डैम है उसकी लुटिया डूब रही है। इसकी तरफ मैंने सरकार का ध्यान दिलाया है और मैं समझता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह भी कह देता हूं कि यह योजना केओटिक और डेस्पौटिक है।

सभापति (श्री रामनारायण मंडल)--एक घोषणा है। ११ तारीख को जो नोट रेडी क्वेश्चन्स हैं उनको लिया जायगा।

श्री रामगुलाम चौधरी--क्या ११ तारीख को भी थर्ड प्लान पर बहस होगी ?

सभापति (श्री रामनारायण मंडल)--उस दिन भी इसके लिये समय दिया गया है।

श्री रामदेनी राम--सभापति महोदय, हमारे लिये भी आपके हृदय में जगह थी इसके लिये धन्यवाद है। तीसरी पंचवर्षीय योजना पर जो बहस चल रही है उसमें पहले मैं एग्रीकल्चर के बारे में कहूंगा और उसके बाद और विभागों के बारे में भी कुछ कहूंगा। जैसा कि हमारे श्री यदुनन्दन तिवारी जी ने कहा कि सरकार की मन्शा है कि उत्तर बिहार में एग्रीकल्चर और दक्षिण बिहार में इंडस्ट्री को सरकार डेवलप करना चाहती है, मैं समझता हूं कि सरकार को अपनी मन्शा को बदल देना चाहिये। जो-जो नदियां छोटानागपुर में हैं (स्लो हिली एरिया में जो नदियां निकलती हैं) उनमें वियर बनाना गलत है बल्कि उसमें रिजर्वायर का प्रबन्ध होना चाहिये। हजारीबाग और संथाल परगना में बुलडोजर की दो युनिटें चल रहे हैं। मेरा यह रीक्वेस्ट है कि थर्ड प्लान में पलामू के लिये भी और खासकर सदर सबडिविजन और गढ़वा के लिये एक युनिट दिया जाना चाहिये।

पी० डब्लू० डी० के अन्दर सरकार से मेरा यह रीक्वेस्ट है कि अभी ७५ मील से कम रोड के लिये इसमें प्रबन्ध किया गया है। वहां की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं यह आपसे कहता हूं कि इससे हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। दो ही रोड डेवलपमेंट कमिटी के द्वारा पास हुआ है। उसमें गढ़वा से कांडी रोड की प्रायरिटी मिली है। वहां की स्थिति अगर आप जाकर देखें तो पता चलेगा कि ५० वर्ष पहले जो

वहां की हालत थी वही आज भी है। इसलिये गढ़वा-कांडी रोड को पी० डब्लू० डी० रोड डिक्लेयर कर के उसका काम जल्द शुरू कर दिया जाय। इसलिये मैं चाहता हूं कि गढ़वा रोड को जल्द-से-जल्द पी० डब्लू० डी० अपने हाथ में ले ले और उसको बनाने के काम को शुरू कर दें। डालटेनगंज जिला हेडक्वार्टर्स है और दिनोदिन बढ़ता जा रहा है। यह कोयल नदी के किनारे है और नदी के उस पार चैनपुर है। इसलिये कोयल नदी में एक कौजवे बनाने की बहुत जरूरत है जिसमें लोगों को आने-जाने की सुविधा हो। इसके बाद पक्का-मार रोड जो चपला से रानीगंज जाती है उसको भी तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में लिया जाना चाहिये।

हमारा छोटानागपुर का इलाका जंगली इलाका है और जंगल को बढ़ाने के लिये बहुत-सी जमीन आसपास की एक्वायर कर ली गयी है। अगर किसान उस जमीन पर खेती करने जाते हैं तो उनपर केस चला दिया जाता है और उधर एफोरेस्टेशन भी नहीं होता है। सरकार को चाहिये कि जल्द-से-जल्द एफोरेस्टेशन का काम जारी करे और नहीं तो किसानों को जोतने और खेती करने लायक जमीन पर खेती करने दें। अगर खेती न हो तो जल्द-से-जल्द एफोरेस्टेशन होना चाहिये जिसमें जंगल से सरकार को कुछ आमदनी हो और जो कमी है वह पूरी हो।

इसके बाद मुझे यह कहना है कि हमारे पलामू जिले में कुटीर उद्योग की बड़ी कमी है। वहां पर बांस, लकड़ी, हड्डी, सबाई घास और चमड़ा बहुतायत में मिलते हैं और उनसे वहां पर कुटीर उद्योग चलाया जा सकता है।

सभापति (श्री रामनारायण मंडल)—अभी माननीय सदस्य श्री रामरतन सिंह ने फ्लोर क्रास किया है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिये।

श्री राम रतन सिंह—मुझसे भूल हो गयी है। माफ किया जाय।

सभापति (श्री रामनारायण मंडल)—अच्छी बात है। माननीय सदस्य का अब एक मिनट समय और बाकी रह गया और इसी में उनको समाप्त करना चाहिये।

श्री रामदेनी राम—अब मैं वहां पर हरिजनों की जो समस्या है उसकी तरफ सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूं। अभी वहां पर जो हरिजन हैं न उनके रहने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है और न पहनने के लिये कपड़ा ही मिलता है। अभी वहां के हरिजन छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती है वह भी बहुत कम है और उसको अधिक-से-अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।

उकहो एक नदी है जिसमें बांध बंधवाने के लिये बराबर आश्वासन मिलता है लेकिन आज १० या १२ वर्ष से इसकी ओर कोई कारवाई नहीं हो रही है। सरकार का ध्यान इसकी ओर जाना चाहिये।

सभापति (श्री रामनारायण मंडल)—आपका समय खतम हो गया। आप अब बैठ जाइये।

श्री रामदेनी राम—समय खतम हो गया, इसलिये मैं इतना ही कह कर बैठ जाता हूं।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा—सभापति महोदय, प्रथम योजना का कुछ काम बाकी रह गया यानी उसका काम पूरा नहीं हो पाया कि द्वितीय योजना शुरू हो गयी और फिर द्वितीय योजना का काम पूरा नहीं हो पाया कि तृतीय योजना शुरू हो रही है और इस पर सदन में वाद-विवाद चल रहा है। जब हम यह देखते हैं कि एक योजना का काम पूरा नहीं हो पाता है और दूसरी और तीसरी शुरू हो जाती है और फिर चौथी योजना का काम बढ़ाते जायेंगे तो हम कैसे रहेंगे। योजनाओं पर रुपये खर्च हो रहे हैं, और इसी पर सारी चीजें निर्भर करती हैं। इसपर हम रुपये बरबाद कर रहे हैं और कर्ज बढ़ाते जा रहे हैं जिसके चलते नये कर हम लगाते जा रहे हैं। उप-मंत्री महोदय ने बताया कि ४१ करोड़ रुपये नये कर इस तृतीय योजना को पूरा करने के लिए लगाया जायेगा। सभापति महोदय, प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में लोगों पर कर लगाये गए जिनमें कुछ कर ऐसे हैं जिनको अभी लागू तक नहीं किया गया है। इस प्रकार से कर पर कर लगाते जाने से हमारे प्रान्त के लोगों की कमर टूट जायेगी। जब मैं प्लैन को देखता हूं तो दो विषय हमारे सामने आते हैं, एक है प्राइस लेवेल और दूसरा है अनइम्‌लायमेंट। मैं कहना चाहता हूं कि दोनों चीजों को अच्छी तरह से देखा नहीं गया और इसके सोलुशन के लिए उचित उपाय नहीं किया गया। फिर भी हम देखते हैं कि कृषि पर २४ प्रतिशत खर्च है। मैं चाहता हूं कि कृषि की पैदावार बढ़े जिससे किसान लोग खुशहाल हो जायं उनकी तरक्की हो और वे फलें-फूलें और पुष्पित हों। हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और लैंड डेवलपमेंट पर २४९९.५९ लाख खर्च होगा, सुगर रिसर्च पर २६.९६ लाख और केन डेवलपमेंट पर ८३.२६ लाख होगा। फिर भी यह काफी नहीं है। और इतना खर्च करने पर भी सब किसानों की तरक्की नहीं हो सकती है और वे अधिक-से-अधिक पैदावार नहीं बढ़ा सकते हैं। ईख के खेत में विकास लाना जरूरी है जिससे हम विदेशों में चीनी भेज सकें और किसान खुशहाल रह सकें। मैं देखता हूं कि नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और मार्च में जो किसान ईख का तौल मिलों में करवाये थे उनको आजतक मिल मालिकों ने कीमत नहीं दिया है। मैंने जब प्रश्न किया था तो उसमें यह जवाब मिला था कि २½ करोड़ रुपये किसानों के बाकी हैं, पर मैं देखता हूं कि आज इसका पेमेंट नहीं किया गया और यह बाकी ही है। साउथ बिहार में बिहटा एक चीनी मिल है जिसके यहां किसानों के ८ लाख रुपये बाकी हैं। जिसका अगर सूद ६½ प्रतिशत के हिसाब से जोड़ा जाय तो ५०,००० हो जाता है। तो किसान के रुपये अटके हुए हैं और उनको पेमेंट नहीं किया जा रहा है। तो कैसे आप रख सकते हैं कि किसानों को रुपये भी न मिलें और खेती के काम में डेवलपमेंट करें। ४ मई को इसी सदन में मैंने एक कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया था जिसके जवाब में पंडित विनोदानन्द झा ने आश्वासन दिया था कि १५ दिनों के अन्दर इनका पेमेंट कर दिया जायेगा, लेकिन मैं देखता हूं कि वह अभी पेमेंट नहीं किया गया है और बाकी ही है। केन कंट्रोल एक्ट, १९५५ के अनुसार किसानों के ईख के दाम का चुकता १४ दिन के अन्दर कर देना है, पर ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा कानून में प्रोविजन रहते हुये भी सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। मेरी समझ में नहीं आता है कि क्यों नहीं पेमेंट हो जाता है। मैं देखता हूं कि सरकार को मिल मालिकों से गठबंधन है और यह सरकार मिल मालिकों के हाथ की कठपुतली बन गयी है और इसी कारण से किसानों के काम नहीं हो पाते हैं। तो आप ही समझ लें कि ऐसी हालत में किसान कैसे खेती की तरक्की कर सकते हैं। सभापति महोदय, सीड मल्टीप्लीकेशन एन्ड डिस्ट्रिब्यूशन पर ५६४.३९ लाख रुपये खर्च होने वाला है। हर प्रखंड में २५ से लेकर ४० एकड़

तक जमीन ली गयी है अच्छे बीज को तैयार करने के लिए जिससे कि पैदावार बढ़े और किसानों को प्रोत्साहन मिले । किसानों को प्रभावित करने के लिए और खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए बीजवर्द्धन केन्द्र की स्थापना की गयी है ।

पालीगंज एक प्रखंड है पटना जिले में जिसमें जमीन ली गई है २९ एकड़ ८५ डिसमल। १९५९-६० में इसपर खर्च हुआ ९,००० रुपया इससे आय हुई ४,८२४ रुपया और घाटा हुआ ४,१७६ रुपया । यह आंकड़ा हमें सरकार से २३ फरवरी १९६१ को उपलब्ध हुआ है हमारे एक प्रश्न के उत्तर में । फिर जहां किसान अधिक पैदा करते थे वहां का हाल यह है कि धान की फसल ३५६ मन २० सेर हुई है और जब किसानों के जिम्मे यह खेत थे तो इसमें पैदा होता था १,२८० मन ।

सभा शुक्रवार, तिथि ६ अक्तूबर १९६१ के ११ बजे दिन तक स्थगित की गई।

पटना:

तिथि ५ अक्टूबर, १९६१ ।

एनायतुर रहमान,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।